



कर्नाटक: डबल इंजनियों की सांप्रदायिक पैतरेबाजी

राजेंद्र शर्मा
वास्तव में, 2014 के आम चुनाव में "अच्छे दिन" के अपने साथ

वादों के बावजूद, नरेंद्र मोदी ने सांप्रदायिक ध्वनीकरण के मुद्दों से भी खास परहेज नहीं किया था। इसीलिए, जहां उनके प्रचार अधियान में कथित "पिंक रिवोल्यूशन" पर (यानी मांस के कारोबार के नाम से मुसलमानों पर) हमले के बहाने, आम तौर पर मुस्लिमविरोधी भावनाओं को सहलाया गया था, तो 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों के सधी-भाजपायी आरोपियों को उनकी सेवाओं के लिए, उनके खिलाफ मामले दर्ज होने के बावजूद, चुनाव में तथा चुनाव के बाद भी, बखूबी पुरस्कृत किया गया था। कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के आखिरकार, खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक-धार्मिक नारों का सहारा लेने पर उत्तर आने पर, जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता था, चुनाव आयोग के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी है। लेकिन, यह मोदी निजाम में भारतीय जनतंत्र से लोगों की अपेक्षाओं को जिस रसातल में पहुंचा दिया है उसी का बयान करता है कि कर्नाटक में भाजपा की मुख्य-प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस समेत, दूसरी किसी भी उल्लेखनीय राजनीतिक ताकत ने, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत तक करना जरूरी नहीं समझा है कि मोदी का कर्नाटक में अपने चुनावी प्रचार में बजरंग बली के भक्तों और विरोधियों के आधार पर, राजनीतिक-चुनावी विभाजन की दुहाई देना और अपनी सभाओं में बार-बार मतदाताओं से "बजरंग बली की जय बोलकर" वोट डालने की अपीलें करना, सीधे-सीधे धर्म के नाम पर वोट मांगना है, जो भारतीय चुनाव कानून के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्जित है। पर जब सुनवाई की ही उम्मीद न हो, तो फरियाद करने की बेसूट मेहनत भी कौन करेगा? इसे बिंदबां ही कहा जाएगा कि इस प्रसंग में शिव सेना के मुखिया, उद्घव ठाकरे पर ही यह याद दिलाने का जिम्मा आया कि एक समय था जब "हिंदू" होने की दुहाई के सहरे वोट मांगने के कारण, उनके पिता बाल ठाकरे से चुनाव आयोग ने दंडस्वरूप "मताधिकार" ही छीन लिया था! लगता है कि मोदी राज में नरेंद्र मोदी पर, सामान्य लोगों तथा खासतौर पर विपक्षी पार्टियों पर लागू होने वाले नियम-कायदे लागू ही नहीं होते हैं। लेकिन, यह कर्नाटक में अपने धूंआधार चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में, चुनावी बाजी हाथ से निकलती देखकर मोदी के "बजरंग बली" के जैकारों का सहारा लेने का या अपने राजनीतिक-चुनावी विरोधियों को 'बजरंग बली विरोधी' बताने के जरिए, धार्मिक दुहाई को राजनीतिक-चुनावी हथियार बनाने भर का भी मामला नहीं है। इसे चुनावी तरकश का तीर बनाए जाने का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। संदर्भ है कि कांग्रेस के कर्नाटक के चुनाव घोषणापत्र में इसका बाद किए जाने का कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने तथा हिंसा करने वाले संगठनों पर रोक

શરૂ

અરવિન્દ મોહન

મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ ઔર ભાજપ ઇસ ઉપલબ્ધ કો રાજનૈતિક રૂપ સે ભૂમાળ કા પ્રયાસ કરેરો યા નહીં, ક્યોંકિ અભી હાત તક પ્રદેશ કે અધિકાંશ હિસ્સોં મેં શરાબ પીના એક સમાજિક બુરાઈ કે રૂપ મેં દેખ જાતા થા। હોલી દિવાળી પર ભી બહુત ક હી લોગ શરાબ પીતે થે। ઔર યાં ફૌજિયાં તથા કુછ ખાસ મુશ્કિલ કામ કરને વાલું કે પીને ભર કી ચીજ માની જાતી થી। યાં હિસાબ લગાના મુશ્કિલ હૈ કિ લોગોં દ્વારા ત્યાં જાને વાલી શરાબ જ્યાદા જ્વલનશીલ હૈ રૂંડ હમારી રાજનૈતિક મેં ઇસે લેકર ઉઠાને વાત બવાલ પર યાં કહને મેં કોઈ મુશ્કિલ નહીં હૈ કિ અભી દસ સાલ પહેલે તક ઇન દોનો મોર્ચાં પર શરાબ કી 'પ્રતિષ્ઠા' ઇતની ન થી ભાં, ગાંજા, તંબાકુ-હુકવા વાગેરહ કા ચલતો થા લેકિન જ્યાદા ન થા ઔર ઉન્હેં લેકિન બહુત હંગામા નહીં થા। સાધુઓં કો છોડે તો આમ લોગોં મેં સે જો કાઈ ઇનકા સંવાદ કરતા થા વહ કુછ અપરાધ ભાવ સે હું કરતા થા। ઔર આજાદી કી લડાઈને સાથ ગાંધી ને શરાબ ઔર નશામુક્તિ કી મુહિંદું છેડકર ઇસ સવાલ પર ઇસકા સેવન કરાવાલોં કો ઔર ભી જ્યાદા રસ્થાત્મક મુશ્કિલ અપનાને કો મજબૂર કર દિયા। ઔર ઉસ પ્રભાવ મેં ગુજરાત ઔર મહારાષ્ટ્ર કે વધ જિલે મેં શુરૂ સે, ઔર અન્ય રાજ્યોં મેં ખુલ્લે શરાબવંદી હોતી રહી હૈ। 1977 કી જનની સરકાર ને તો ઇસે દેશ કે સ્તર પર લાગુ કરું કા અસફલ પ્રયોગ કિયા। શરાબ કે નશે સે પીડિત પરિવારોં કી ઔરતોં કે દબાવ રે અનેક રાજ્યોં મેં શરાબવંદી લાગુ હુંદી ઔર ફિર રાજસ્વ કે દબાવ તથા નકલી શરાબ વેનું કહર કે ચલતે શરાબવંદી ઉઠતી ભી રહી હૈ બિહાર મેં જસ્તુ નીતીશ કુમાર ને બિના કિસ્સે આંદોલન કે દબાવ સે અપની સોચ તે અમારા જગતની કી હૈ શ્રીમતી અનુસાર ભાગ તુલના

छाता पर टाक कर, तत्काल इस चुनाव में हड्डुत्वावाद सप्रदायक ध्वनीकरण करने का भी साधन है।

बजरग दल पर प्रतिबंध के कारण

कर दिया है! बुनियाद मुझे आर भाजपा सरकार की असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी का यह चिर परिचित नुस्खा है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिवंध लगाने का वादा क्यों किया है? क्या बजरंग दल कोई आतंकी संगठन है? क्या इसकी गतिविधियां समाज और राष्ट्र विरोधी हैं? बजरंग दल एक स्वयंषित हिंदूवादी संगठन है। यह देश में हिंदुओं का 'सुधार' करके गैर हिंदुओं के खिलाफ नफरत और हिंसा का प्रयोग करता रहा है। आरएसएस अपनी स्थापना (1925) के समय से ही वर्ण और जाति पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखता रहा है। भारत के संविधान और लोकतंत्र में आरएसएस का भरोसा कभी नहीं रहा। उसकी अपेक्षा थी कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की तरह उसे भी अंग्रेज सरकार द्वारा हिंदू राष्ट्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आजादी के बाद विशेषकर जवाहरलाल नेहरू और बबा साहब भीमराव अंबेडकर

का मजबूत हाता स्थान आर दश म बढ़ता सोशलिस्ट राजनीति से आरएसएस चित्तित था। अगर पिछड़ी जातियां सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त होती तो जहिर है, द्विज जातियों के सांस्कृतिक वर्चंस्व को चुनाती मिलती। इसलिए आरएसएस ने धर्म और आस्था के आधार पर शूद्रों-पिछड़ों को जोड़ने और इनकी ताकत को मुखलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई। बजरंग दल जैसे संगठन की नींव इसी विचार पर आधारित थी। जनसंघ के स्थान पर 1980 में बनी भाजपा ने 'गांधीवादी समाजवाद' को अपना आदर्श बनाया। इस विचार के आधार पर दलित और पिछड़ों को संघ आकर्षित करना चाहता था। इसके बावजूद भाजपा और आरएसएस ने बहुत रणनीतिपूर्वक राम मंदिर आंदोलन को अपना राजनीतिक एजेंडा बनाया। 1 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के सभा घर से सभा में बहां तरीके स्थान

केन्द्र जम्मू-कश्मीर में लिथियम खनन की नीलामी के लिए बेकरार



बार म कुछ भा खुलासा नहीं किया गया है। क्या उनमें विदेशी 'निजी कंपनियाँ' शामिल हैं? जमू-कश्मीर एक अशांत राज्य है और सीमा पार आतंकवादी हमलों का एक पसंदीदा लक्ष्य है। सरकार निजी उद्यमियों को लिथियम और अन्य अलौह धातुओं का खनन करने के लिए किस तरह की सुरक्षा प्रदान करेगी? कई देशों ने लिथियम खनन का कार्य राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को इस आधार पर सौंपा है कि यह एक रणनीतिगत खनिज है। चैक्की भारत के पास लिथियम खनन में कोई विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए दुनिया के कुछ शीर्ष लिथियम खनिकों और प्रोसेसर को राज्य क्षेत्र के भागीदारों के रूप में शामिल करना सही हो सकता है। अब तक, भारत के संभावित लिथियम भंडार उत्पादनक प्रतीत होते हैं। दुनिया भर में लिथियम के कुल भंडार का अनुमान केवल 26 मिलियन टन है। नए भंडार की खोज के लिए सर्वेक्षण जारी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, बोलीविया में दुनिया में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले लिथियम संसाधन हैं। पर्याप्त भंडार वाले अन्य देशों में अर्जेटीना, अमेरिका, चिली, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और जर्मनी शामिल हैं। लिथियम वर्तमान में हार्डरॉक या नमकीन खानों से उत्पादित होता है।

हार्डरॉक खानों से उत्पादन के साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। अजेंटीना, चिली और चीन मुख्य रूप से इसका उत्पादन नमक की झीलों से करते हैं। मार्च में ऑस्ट्रेलियाई उद्योग, विज्ञान और संसाधन विभाग की संसाधन और उर्जा तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक उत्पादन 2022 में 737,000 टन लिथियम कार्बोरेंट समतुल्य (एलसीई) था और 2023 में 964,000 टन और 2024 में 1,167,000 टन तक पहुंचने का अनुमान है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण उद्योग के विकास को आकार देने में इस खनिज के महत्व को देखते हुए, चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने कहा कि वह देश के लिथियम उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं और धातु का उत्पादन करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी बनाना चाहते हैं। चिली के राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य के लिथियम अनुबंध केवल राज्य नियंत्रण के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में जारी किये जाएंगे। चिली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक है। वैश्विक लिथियम उत्पादन में लगे प्रमुख कॉर्पोरेंट उद्यमों में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की टैलिसन लिथियम शामिल है, जो एक संयुक्त उद्यम फर्म है,

तकनाका-
पादन क्षमता
वर्ष है।
स्ट्रेलिया में
30,000 टन
न करता है,
हैं जिससे
मिलियन टन
रप्पनियों में
समूह के
सप्तरेस, जो
दण्डयुमिन का
2023 की
0,000 टन
योजना है।
चिली के
टीटीआटाकामा
रेन्ट प्रति वर्ष
2024 तक
तक बढ़ाने
लंग लिथियम
पॉजुएलोस-
0,000 टन
करेगा, और
0 टन तक
खनन और
ज्ञान और
में रखते हुए,
उद्यमी को
उसके साथ
जो नियांत
केन्द्रित रहे।
शुरू करना
रपनियों को
बनन नीलामी
का निर्णय
है। सरकार
जम्मू और
में जैखिम
र सकती है।
इंडस्ट्री के
कश्मीर के
द से कश्मीर
ब डॉलर से

शराब के मामले का छुपा रस्तम कौन

अरविन्द मोहन
मालांडी योगी

कराड़ रुपए को पार कर गया है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में अभी हाल तक शराब की पैठ काफी कम मानी जाती थी। राज्य में देश की कुल खपत का मात्र पांच फीसदी हिस्सा ही शराब खपत होती थी। अब चार साल में यह दस फीसदी पहुंच गई है अर्थात् चार साल में 200 फीसदी की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा बृद्धि बिहार की खपत में हुई है जो 350 फीसदी से भी ज्यादा है। अगर शराब कंपनियों के हिसाब से देखें तो कई की बिक्री में चार सौ फीसदी तक की बढ़तरी हुई है। कई ब्रांडों की बिक्री में उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक प्रांत बन चुका है। अब यह कहना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा इस उपलब्धि को राजनैतिक रूप से भुनाने का प्रयास करेगी या नहीं, क्योंकि अभी हाल तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शराब पीना एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता था। होली दिवाली पर भी बहुत कम ही लोग शराब पीते थे। और यह फैजियों तथा कुछ खास मुश्किल काम करने वालों के पीने भर की चीज मानी जाती थी। भांग, तंबाकू और गांजा को वैसी बुराई नहीं माना जाता था। पर अब सरकार ने प्रदेश में शराब की बिक्री सबसे लिप्त आसान कर दी है। जिस कंपनी को इच्छा हों वह आए, एक मोटी रकम भरे और थोक बिक्री शुरू कर दे। इसके साथ ही सरकार डंडा लेकर रखवाली करती है कि कोई दूसरा बिना पैसे दिए माल न बेच पाए। नकली शराब की बिक्री पर सख्ती है और ई-गवर्नेंस की मदद से चुस्ती बरती जा रही है। इन सबमें हर्ज नहीं है, बर्शें ऐसी चुस्ती शासन के अन्य मामलों में भी दिखे और ऐसा ही रिजल्ट दूसरे मामलों में भी दिखे। सिर्फ शराब की बिक्री में दिन दूनी रात चौगुनी की बढ़त दिखे तो शर्म का विषय होगा जानिए।

इस्तिहार जैसी राजनीति की कहानियां

आरएसएस की सोच पर आधारित
झूठ और कपट से भरी है फिल्म
केरल स्टेरीइस दौर में याद आती
है जिमी कार्टर की मूल्यगत
राजनीति
मशहूर शायर बशीर बद्र का शेर
है- मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये
मोहब्बतों की कहानियाँ
जो कहा नहीं वो सुना करो, जो
सुना नहीं वो कहा करो
इसमें थोड़ा फेरबदल कर अगर
मोहब्बत की जगह राजनीति करने
की गुस्ताखी की जाए, तो आज के
माहौल में यह शेर बिल्कुल फिट
बैठता है। मौजूदा दौर की सियासत
में ऐसी ही कहानियाँ चल रही हैं।
कहा कुछ जाता है और आशय
कुछ और होता है। और जो असल
मक्सद होता है, वो कभी सीधे
शब्दों में बयां नहीं किया जाता।

राजनैतिक बजिर्यां कैसे पलटी जाती हैं, इसके कुछ उदाहरण हाल ही में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में राकांपा के मुखिया शरद पवार ने पहले इस्तीफा देने का ऐलान किया, जिससे उनके समर्थक भावुक होकर उनसे पद पर बने रहने की अपील करने लगे। राजनीति और दल में उनका क्या ओहदा है, राज्य को उनकी कितनी जरूरत है, इसकी व्याख्याएँ की जाने लगीं। राकांपा की बैठकों का दौर चला और शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया गया। और फिर शरद पवार ने अपने समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस्तीफा वापस ले लिया, अब वे फिर से राकांपा के प्रमुख हैं। श्री पवार के इस कदम से एक तरफ उनकी बेटी बजोंकी शरद पवार के बाद पार्टी की कमान उन्हें ही देने की संभावनाएँ सबसे अधिक जतलाई जा रही थीं। और दूसरी तरह भतीजे अजीत पवार को यह सख्त संदेश दे दिया गया कि अगर वे पार्टी और पार्टी सुपीमो के खिलाफ जाएंगे, तो उनके राजनैतिक भविष्य के लिए सही नहीं होगा। राकांपा में कोई उन्हें स्वीकार नहीं करेगा और भाजपा में भी उन्हें सम्मानजनक स्थान नहीं मिलेगा। अगले चुनावों के पहले पार्टी की अंदरूनी खटपट को शरद पवार ने बड़ी चालाकी से शांत करा दिया। कुछ ऐसा ही खेल अब राजस्थान में हुआ है। बल्कि यहां तो अशोक गहलोत ने अपने खिलाफ उठ रहे बगाबती सुरों को शांत करने के साथ विपक्षी दल भाजपा के लिए

